>

Title: Need to ensure proper compensation to the farmers whose lands are being acquired by a private company to set up a thermal power station in Bansi block of Banka in Bihar.

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): सभापति महोदय, अभी सदन के अंदर देश की खेती को सूखे बचाने और जल स्रोतों के निर्माण की चर्चा हो रही थी। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार के बांका के बौंसी प्रखंड में अभीजीत ग्रुप द्वारा थर्मल विद्युत स्टेशन के निर्माण की अनुमति मिली है। थर्मल को 2200 एकड़ जमीन की आवश्यकता है जिसे राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को किसानों से जमीन खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा जमीन का स्वयं अधिग्रहण न कर कम्पनी को जमीन खरीद की अनुमति देना किसानों के लिए भयानक हादसा साबित हो रहा है। किसान थर्मल विद्युत गृह के निर्माण के विरोधी नहीं हैं मगर अपनी जमीन की उचित कीमत चाहते हैं। कम्पनी द्वारा किसानों से वार्ता कर उचित कीमत न दे कर स्थानीय गुंडे एवं माफियाओं द्वारा भय का वातावरण तैयार कर जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसका समर्थन कहीं न कहीं से राज्य सरकार से प्राप्त है। जहां बिहार राज्य में अन्य स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण स्वयं सरकार के द्वारा 20 से 25 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जा रहा है, वहीं बौंसी में मात्र 40-50 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीन को लूटा जा रहा है। अनाथ, विधवा तथा अनपढ़ असहाय ग्रामीणों को ताकत एवं मार-पीट के बल पर जबरदस्ती निबंधन कार्यालय में ले जा कर अंगूठे का निशान बनवाकर निबंधन की खानापूर्ति की जा रही है। हद तो तब हुई जब गैर व्यक्ति जिनके पास ताकत है सैकड़ों किसानों को डरा धमका कर पावर ऑफ एटार्नी लिया गया एवं उनकी जमीन को औने-पौने दाम पर स्वयं निबंधित कर दिया गया तथा बदले में कीमत भी नहीं दी गई है। जो जमीन किसी भी हालत में नहीं देना चाहते हैं बिना निबंधन के ही जमीन पर कब्जा कर लिया जा रहा है। बौंसी की घटना अपने आप में देश की अनोखी घटना है। ताकत के आधार पर जमीन पर कब्जा देश के किसी भी प्रदेश में नहीं किया गया है। जमीन के साथ अनर्थ इस हद तक गया है कि चानन जलाशय का पानी भी कम्पनी को सुपुर्द कर दिया गया है। चानन जलाशय 50 वर्ष पुराना है जिससे बड़े भू-भाग की उपजाऊ जमीन की सिंचाई होती है। किसान बेचैन हैं। कोई भी आगे बढ़ कर किसानों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है, जिससे वे आंदोलन करने पर उतर आए हैं। आंदोलन जमीन और पानी को ले कर तीखा होता जा रहा है। आवश्यकता जमीन की उचित कीमत दिलाने तथा सिंचाई के पानी को बचाने की है। आंदोलन पश्चिम बंगाल के सिंगूर की तरह खतरनाक बन जाए, उसके पूर्व हस्तक्षेप करना आवश्यक है।

मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करके किसानों के हितों की रक्षा की जाए तथा उनके पानी और जमीन को लूट से बचाया जाए।